प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और नृत्य निर्देशिका, राज्यसभा की प्रथम मनोनीत महिला सदस्य, पद्म भूषण से सम्मानित रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

——— केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

संक्षिप्त खबरें

छात्रों को दिए टैबलेट

नई दिल्ली । शालीमार बाग के एएच ब्लाक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बी में जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन के सौजन्य से टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निशुल्क टैबलेट और पुस्तकें वितरित की गई। समारोह में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सूबेदार यादव ने छात्रों को वर्तमान समय में शिक्षा में तकनीक की आवश्यकता से अवगत कराया। इस मौके पर फाउंडेशन के सदस्य सत्या शर्मा, तरुण गर्ग, अशोक कुमार, नवीन सिंह,अनीता शर्मा, रचना माथुर सोनिया बाजपेई प्रिया कुमारी और नीरज आनंद उपस्थित रहे।

दुख जताया

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध पीजीडीएवी सांध्य कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ.अनिल कुमार सिंह की अल्प आयु में निधन पर आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने गहरा जताया है। डीटीए ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना एक अच्छा सहयोगी, अच्छा मित्र, वैचारिक व्यक्ति और शिक्षक के साथ ्साथ एक आंदोलनकर्मी खो दिया, जिसकी भविष्य में पूर्ति संभव नहीं है। डीटीए के अध्यक्ष डॉ हंसराज ने दिवंगत डॉ.अनिल कुमार सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ. सिंह हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक उभरते हुए युवा आलोचक थे जिन्हें कविता, कहानी और उपन्यास की समझ थी। उनका कविता के प्रति अगाध प्रेम था, जिसमें हमें गांव की मिट्टी की सुगंध दिखाई देती है। वे लेखन में सक्रिय थे।

महापौर ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय उपायुक्त प्रदीप कुमार, नजफगढ़ जोन के अध्यक्ष सत्यपाल मलिक के साथ सागरपुर वार्ड में विकसित किये जा रहे पार्क, निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग व डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त महापौर ने गांधी मार्किट, सागरपुर में बनायी जा रही डिस्पेंसरी के निर्माण कार्यो का भी जायजा लिया। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता पी.सी मीणा, निदेशक उद्यान विभाग डॉ आलोक सिंह व निगम के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशाला में दी जानकारी

नई दिल्ली । इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी), सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिया पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। समस्या समाधान और आइडिया सत्र के वक्ता आशु अग्रवाल ने कहा कि पहला कदम हमेशा समस्याओं की खोज करना और उनसे वास्तविक समय में निपटना होता है। इस व्यावहारिक कार्यशाला ने न केवल समस्या समाधान के बारे में बात की बल्कि आइडिया और इससे जुड़े विभिन्न चरणों पर दूरदर्शी अनुभव भी प्रदान किया। कार्यशाला के दौरान प्रभावशाली माहौल के चलते जिज्ञासु प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी निरंतर बनी रही। इस क्रम में आईआईसी्जामिया ने इनोवेटर्स की पिचिंग और लिंकेज पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

यूक्रेनी दूतावास के बाहर टहलते लोग। फोटो : प्रेट्र

सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार

नई दिल्ली (भाषा) । रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बिगड़ने पर वहां फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों ने बृहस्पतिवार को सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें छात्रों ने भावुक होते हुए भारतीय अधिकारियों से उनकी वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो को कई प्रमुख हस्तियों ने साझा किया है और सरकार से इस संबंध में कदम उठाये जाने का आह्वान किया है। ऐसे ही एक वीडियो में, यूक्रेन की राजधानी कीव के एक रेलवे स्टेशन पर लगभग 12 दृष्टिबाधित छात्र फंसे हुए देखे गए। एक अन्य वीडियो में, छात्रों को अपने बैग के साथ भारतीय दूतावास के बाहर खड़े देखा गया, जो अधिकारियों से किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनुमान के अनुसार, वर्तमान में 20 हजार से अधिक भारतीय यूक्रेन में रह रहे हैं जिनमें से अधिकतर छात्र हैं ।

कैबिनेट ने ई-वेस्ट इको पार्क बनाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली (एसएनबी) । दिल्ली में भारत का पहला ईव्वेस्ट इको पार्क बनेगा। दिल्ली सरकार का इकोप्पार्क राजधानी में ईक्कचरे के निपटारे का काम करेगा। बीस एकड़ में फैला हुआ ईव्वेस्ट मैनेजमेंट इको-पार्क स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। यहां इनफॉर्मल सेक्टर के ऑपरेटरों को फॉर्मल री-साइकिलिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पहले ईव्वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाने को मंजूरी दी। यह ईव्वेस्ट मैनेजमेंट पार्क वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरणको ध्यान में रखते हुए काम करेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस विषय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीस एकड़ में फैला ये वेस्ट-मैनेजमेंट पार्क स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा, जहां इनफॉर्मल सेक्टर के ऑपरेटरों को फॉर्मल रीस्साइकिलिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां साइंटिफिक और इंटीग्रेटेड तरीके से एक परिसर के अंदर ही ई-वेस्ट को रिसाइकल व रीम्मैनुफैक्चर करने का काम किया जाएगा। साथ ही ईव्वेस्ट को चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

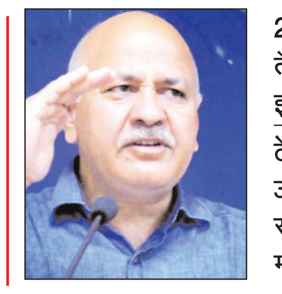

20 एकड़ के क्षेत्र में तैयार होगा ई वेस्ट इको पार्क

टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ बढ़ा ई-वेस्टः मनीष सिसोदिया

उन्होंने कहा कि राजधानी में ईव्वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कई दुर्घटनाओं के होने का खतरा भी होता है। वर्तमान में दिल्ली में हर साल लगभग दो लाख टन ईक्कचरा निकलता है और इसे ज्यादातर इनफॉर्मल रीस्साइकलर्स द्वारा रीस्साईकल किया जाता है। सिसोदिया ने कहा कि इस इकोप्पार्क में कचरे का निस्तारण वैश्रानिक तरीके से किया जाएगा। अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ ईव्वेस्ट इकोप्पार्क एक ही परिसर में प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करने के साथ ईव्वेस्ट को तोड़कर रिसाइकल व री-मैनुफैक्चर का काम करेगा। ई-वेस्ट ईकोप्पार्क में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग और रीस्साइकल यूनिट होंगी ताकि भविष्य में इनसे उत्पादन के लिए सामग्री निकाली जा सके। इस सुविधा का इस्तेमाल उच्च तकनीक के माध्यम से प्लास्टिक रीसाइकलिंग किया जाएगा।

ई-वेस्ट इको पार्क से मिलेंगे ये फायदे : इकोप्पार्क ई कचरा को रिसाइकल करने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करेगा।इको-पार्क पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करेगा और ई-कचरे के रीस्साइकिलिंग के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाएगा ।

दिल्ली दंगा मामले में एक के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली (एसएनबी) । दिल्ली दंगे के मामले में अदालत ने कहा कि उस समय आतंक और डर का माहौल था, जिस वजह से लोग पुलिस के समक्ष आकर अपना बयान देने से कतराते थे। इस वजह से बयान दर्ज करने में देरी हुई तो यह आरोप तय न करने का आधार नहीं हो सकता। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने यह कहते हुए एक आरोपी जावेद के खिलाफ दंगा करने एवं अन्य के तहत आरोप तय कर दिए।

न्यायाधीश ने कहा सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी जावेद के खिलाफ धारा दंगा व घातक हथियार का प्रयोग करने व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य है। हालांकि उन्होंने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया। यह मामला एक स्कूल के आसपास की घटना से संबंधित है जहां दंगाइयों ने विस्फोटक पदार्थो का इस्तेमाल करके हिंसा का सहारा लिया।

आरोपी जावेद के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं : कोर्ट

हिंसा से आम जनता इतनी आहत थी कि कोई भी पुलिस के सामने बयान देने को तैयार नहीं था : कोर्ट

न्यायाधीश ने कहा कि हिंसा के दौरान कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य बेघर हो गए। दंगाइयों ने कई लोगों की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाकर राख कर दिया। दंगों पर काबू पाने के बाद भी महीनों तक पूरी पूर्वोत्तर दिल्ली में आतंक और सदमे का माहौल बना रहा। हिंसा से आम जनता इतनी आहत थी कि कोई भी पुलिस के सामने बयान देने को तैयार नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यक्ति जो हिंसा के गवाह थे, उनसे पुलिस को बयान देने के लिए तुरंत आगे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हिंसक घटनाओं के कारण आम जनता इतनी आहत हो गई थी कि कोई भी पुलिस को बयान देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। पुलिस को दोहरी भूमिका निभानी पड़ी यानी। शांति बहाल करने वालों के साथ्साथ जांच भी की गई। दिल्ली पुलिस को दंगों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया था।

अदालत ने कहा कि पुलिस को शांति बहाल करना के साथ जनता में सुरक्षा की भावना पैदा के अलावा उन्हें दंगों के बाद दर्ज की गई सैकड़ों प्राथमिकी में जांच करनी पड़ी। गवाहों का पता लगाना और अपराधियों का पता लगाना पुलिस के लिए एक कठिन काम था। इन परिस्थितियों में केवल देरी के कारण गवाहों के बयानों को खारिज करना न्याय का उपहास होगा। हालांकि गवाहों ने भी अपने बयानों में उल्लेख किया था कि दंगों के कारण, उनके पड़ोस में माहौल बहुत प्रतिकूल था और दोनों समुदायों के सदस्य एक्दूसरे से डरते थे। इस डर के कारण ही उन्हें पुलिस से संपर्क करने और अपना बयान देने के लिए साहस की आवश्यकता की पड़ी।

सरकार ईव्वेस्ट के लिए सेंटर स्थापित करे : कपूर

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपम्मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आग्रह किया कि यदि ई-वेस्ट पार्क बनाने की कल्पना को साकार करने के लिए पहले सरकार को ईव्वेस्ट एकीकृत सेंटर बनाने की जरूरत है। जिससे राजधानी भर का ईव्वेस्ट जगह्जगह से एकत्र करके एक जगह लाया जा सके। सरकार को हर वार्ड में इस तरह के सेंटर बनाने चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने तर्क दिया है कि ईव्वेस्ट पार्क को केवल एक जगह ही बनाया जा सकता है। जबकि ईव्वेस्ट पूरी दिल्ली से निकलेगा। इसको एक जगह लाने के लिए जगह्जगह केंद्र बनाने की जरूरत है। जिससे स्थानीय लोग उस सेंटर पर अपना ईव्वेस्ट जमा करा सकें और बाद में उसे ई-वेस्ट पार्क में लाकर नष्ट किया जा सके। इसके बगैर ईव्वेस्ट पार्क की योजना को सफल बनाना मुश्किल होगा। दिल्ली के लोग ईव्वेस्ट का समाधान चाहते हैं।

दिल्ली्एनसीआर में आज होगी बारिश !

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली व एनसीआर में शुक्रवार को हल्की और शनिवार को तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बारिश की संभावना को देखते हुए विभाग ने शनिवार के लिए यलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। वहीं बृहस्पतिवार को दिनभर आसमान में बादलों को डेरा रहा, जिसकी वजह से धूप छांव का खेल चलता रहा।

बारिश को लेकर शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी

बादल होने की वजह से बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग के अपने पूर्वानुमानों में शुक्रवार को यहां का तापमान 26 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इसके साथ ही कल कुछ एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और रात के समय बारिश होने की संभावना बनी हुई है। शनिवार को भी बारिश होगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना जतायी जा रही है।

बृहस्पतिवार की सुबह ठंड के साथ हुई लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप खिली और मौसम में बदलाव देखने को मिला। इसके बाद मौसम का मिजाज गर्म होना शुरू हुआ लेकिन शाम ढलने के साथ ही तेज चलती हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी। मौसम विभाग पहले ही कह चुका था कि इस सप्ताह मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में भी इजाफा होगा। वैसे भी ठंड वापस लौटने की बेला में है, लेकिन जाते्जाते एक बार गिरे तापमान का अहसास कराएगी।

पार्षद गीता रावत और लावारिस पशुओं को लेकर हंगामा

पूर्वी दिल्ली (एसएनबी) । शाहदरा साउथ जोन की बैठक मे सीबीआई द्वारा गीता रावत को रि ात लिए जाने के मामले को लेकर पार्षद राजीव चौधरी ने मामला उठाते हुए कहा कि एक पार्टी जिसका निर्माण एक आंदोलन से शुरू हुआ था और झूठे सपने दिखा कर सत्ता हासिल कर ली । उन्हीं की पार्टी की पार्षद गीता रावत जोन की बैठकों में भ्रष्टाचार का मामला जोर-शोर से उठाती थी ।

शाहदरा साउथ जोन की बैठक

लेकिन खुद ही रि ात लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़ी गई ।इसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार ने कहा कि बैठक में क्षेत्र की समस्याएं उठाएं न कि यह मामला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षद और नेता भी भ्रष्टाचारी है। गीता रावत के मामले को लेकर भाजपा पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर किया तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इसका विरोध किया। काफी देर हंगामे के बाद जोन चैयरमेन हिमांशी पांडे ने मामले को शांत कराया। वहीं बैठक के दौरान पार्षद शशि चांद ने कहा कि उनके वार्ड के पीडब्ल्यूडी के सभी नाले भरे हुए हैं और जल बोर्ड वाले सड़कें खोद देते है लेकिन काम होने के बाद उन्हें ठीक नहीं कराया जाता। पार्षद रमेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर पार्षद लावारिस गायों और कुत्तों की वजह से हो रही परेशानी को लेकर आवाज उठा रहे हैं । लेकिन अधिकारी कह रहे है उनके पास लावाारिस पशुओं को उठाने के लिए एक ही गाड़ी है। वहीं रमेश गुप्ता ने कहा कि अब नशेड़ियों को उठाने के लिए भी निगम को गाड़ियां लेनी होंगी, क्योंकि नशेड़ी शराब पीकर सड़कों पर गिरते पड़ते नजर आ रहे है। पार्षद गोविंद अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत टेबल पर चढ़कर जोर्शोर से आवाज उठाती थीं, लेकिन अब खुद ही रि ात लेते हुए सीबीआई ने उन्हें पकड़ा है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए।

रिसर्च को बढावा दिया जाना चाहिए : एलजी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के साथ वार्षिक रिपोर्ट पर बैठक की। उपराज्यपाल ने इस विश्वविद्यालय के कामकाज का आकलन किया व इसकी एकाउंट प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्याालय द्वारा रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए व उद्योग जगत के साथ सीधा संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही हर्बल दवाओं के उत्पादन पर काम शुरू करना चाहिए। बैठक में इस विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019्20 को पटल पर रखा गया व इसे पास किया गया।

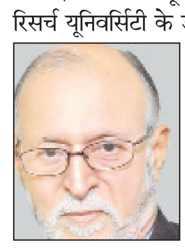

केशवपुर मंडी की हालत जर्जर सरकार ले सुध : सोलंकी

नई दिल्ली (एसएनबी) । पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि चौधरी चेतराम केशवपुर मंडी यहां पर पिछले 20 वर्षो से भी ज्यादा समय से स्थापित है, इसके बावजूद अभी तक इस मंडी को एपीएमसी से एनओसी नहीं मिली है। सोलंकी ने यह बात चौधरी चेतराम की 24वीं पुण्यतिथि पर कही। उन्होंने कहा कि इस मंडी में पानी की सप्लाई भी नहीं है जिससे रोजमर्रा के मजदूर एवं आढ़ती भाइयों के यहां आने पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है।

मंडी को बने 20 साल भी ज्यादा हो गया पर अभी तक पीने का पानी तक नहीं

लोग पानी खरीद कर पीने को हैं मजबूर

अभी तक एपीएमसी से नहीं मिली है मंडी को एनओसी

लोगों को इस्तेमाल के लिए दूरदराज से पानी ढोकर लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में केशवपुर मंडी का नाम प्रसिद्ध समाजसेवी और लंबे समय तक तिहाड़ 28 के प्रधान रहे चौधरी चेतराम जी के नाम पर रखा गया।चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने बताया कि चौधरी चेतराम एक सच्चे समाज सेवक रहे, जिन्होंने लगातार कई वर्षो तक तिहाड़्28 के प्रधान की जिम्मेदारी निभाई। उनके नाम पर ही इस मंडी का नाम रखा गया है, फिर भी यहां इस तरह की दुर्व्यवस्था गाँव देहात की उपेक्षा का प्रमाण है। यहां पीने तक का पानी नहीं उपलब्ध है। बारिश के समय में यहाँ पानी निकासी की कई व्यवस्था न होने से गंदगी और बीमारियां फैल जाती हैं। मंडी के लोगों ने बताया कि बार्बार विधायक एवं सांसद को इस बात की जानकारी दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान तिहाड़ 28 के प्रधान और मंडी के पूर्व चेयरमैन अजय नंबरदार, चौधरी चेतराम के बड़े सुपुत्र धर्मपाल नंबरदार, मंडी के चेयरमैन हर्ष जुल्का, धर्मपाल चंदेला, चौधरी महावीर सिंह असलतपुर मौजूद रहे।

कोरोना के 556 नए केस, छह मौतें

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

राजधानी में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 556 नए मामले सामने आये हैं और छह लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है । राजधानी में संक्रमण दर 1.10 फीसद है । स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि एक दिन पहले की गई जांच की संख्या 50,591 थी, जबकि एक दिन में 618 मरीजों को छुट्टी दे दी गयी । इसमें कहा गया है कि संक्रमितों और मरने वालों की नयी संख्या सामने आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ कर 18,58,154 हो गयी है जबकि मरने वालों की संख्या 26,115 पर पहुंच गयी है । राजधानी में बुधवार को संक्रमण दर 1.05 प्रतिशत थी जबकि तीन लोगों की मौत हुई और कोविड के 583 नये मामले सामने आये थे ।दिल्ली के अस्पतालों में 15,294 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए है जिसमें से 226 पर मरीज हैं ।

जल्द हो इलाज तो बच सकती है बच्चों की आंखों की रोशनी

नई दिल्ली (एसएनबी)। आंखों की देखभाल की दिशा में काम करने वाली नॉनप्रॉफिट संस्था ऑर्बिस इंटरनेशनल ने शीर्ष स्तरीय पीयर्रिव्यूड मेडिकल जर्नल पीएलओएस वन के नए अंक में प्रकाशित नवीनतम रिसर्च के निदेशक व लेखक डा. ऋषि राज बोरह ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा बच्चे अंधे हैं। इनमें से आधे से अधिक मामलों में शुरुआती हस्तक्षेप और इलाज से बच्चों की आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। मोतियाबिंद भी भारत में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हम गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल तक पहुंच बढ़ा दें, पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि परिवारों को उस देखभाल तक पहुंचने से कौन रोकता है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए काम करें, और उन कारकों को दोगुना करें जिनके परिणामस्वरूप ज्यादा बच्चों को उनकी ज़रूरत की देखभाल मिल रही है।

अध्ययन में बच्चों की आंखों की देखभाल में तीन प्रमुख बाधाएं सामने आईं

इलाज में खर्च, जागरूकता की कमी, व इलाज के लिए लंबी यात्रा या अप्वाइंटमेंट में इंतजार की वजह से खो देते हैं बच्चे आंखों की रोशनी

स्टडी का निष्कर्ष : स्टडी में आंखों की देखभाल में तीन प्रमुख बाधाएं सामने आई हैं। आवाजाही और काम से छुट्टी लेने जैसे संबंधित खर्चों के कारण, लागत, माहौल और संसाधन आदि सर्जरी मुफ्त में उपलब्ध होने पर भी इलाज में बाधा डालते हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं जो मोतियाबिंद या इसके इलाज के लिए और सर्जरी का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को पेश नहीं करती हैं। तनाव जैसे कि अस्पतालों की लंबी यात्रा या अप्वाइंटमेंट के लिए इंतजार करने का समय भी इलाज़ में बाधा डालता है।आध्यात्मिकता और पुरानी प्रथाओं पर आधारित सांस्कृतिक विश्वासों पर परिणामों के बारे में विश्वास करना, स्थानीय डॉक्टरों से देखभाल की मांग करना, सर्जरी के बाद नकारात्मक परिणामों के बारे में चिंता, नेत्र देखभाल में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में कम जानकारी आंखों की देखभाल में बाधा डालती है। बच्चों की आंखों की देखभाल को कम प्राथमिकता देने वाले सांस्कृतिक मानदंडों वाले सामाजिक प्रभाव और माता्पिता के लिए हर्बल इलाज़ जैसे वैकल्पिक उपचारों को आजमाने का सामाजिक दबाव भी मोतियाबिंद दिक्कतें हैं।

आंगनबाड़ीकर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी

नई दिल्ली (एसएनबी)। आंगनबाडी कर्मचारियों के संगठन दिल्ली स्टेट आंगनबाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने दिल्ली के समाज कल्याणमंत्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा आंगनबाडी कर्मियों के मानदेय में इजाफा किये जाने की घोषणा पर अपने बयान जारी करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों का हड़ताल जारी रहेगी।

यूनियन की शिवानी कौल ने कहा कि मंत्री जी ने जो कहा कि उनकी कुछ एक यूनियन से बातचीत हुई है जिसके बाद मानदेय बढाये जाने की बात कही है, तो हमारा सवाल है कि वह कौन सी यूनियन है जिससे मंत्री जी की बातचीत हुई है और दूसरी बात यह है कि आंगनबाडी कर्मियों की एक ही यूनियन है और इस यूनियन की 31 जनवरी से हड़ताल चल रही है। हमसे बातचीत किए बगैर सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला हमें मान्य नहीं है और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मंत्री ने आंगनबाडियों को 1500 रुपए मोबाइल का बिल भी दिये जाने की बात कही गई है। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा कि हम इन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे क्योंकि यह दिन में तीन घंटे काम करती है। शिवानी ने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ है। हमसे आठ्आठ घंटे से भी ज्यादा काम लिया जाता है। कोरोना काल में हमसे काम लिया गया, फिर भी इस तरह की बात कहना गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी हड़ताल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कहना कि सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली सरकार ही आंगनबाडी कर्मियों को दे रही है सरासर झूठ है।

नया रखरखाव शुल्क लगा कर शोषण कर रही सरकार : गुप्ता

नई दिल्ली (एसएनबी) । दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि राजधानी की केजरीवाल सरकार नया रखरखाव शुल्क लगा कर उद्योगपतियों का शोषण कर रही है। भाजपा ने सरकार के निर्णय की आलोचना की है और इसके विरोध में अभियान चलाने को कहा है।

इस विषय में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ओखला, नारायणा, मायापुरी, कीर्ति नगर आदि औद्योगिक क्षेत्र चार से पांच दशक पूर्व विकसित किए गए थे और समय के साथ इनमें अधिकांश औद्योगिक प्लाटों को उद्योगपतियों ने भारी भरकम शुल्क देकर फ्री होल्ड करवा लिया है। इसके अतिरिक्त यह सभी उद्योगपति दिल्ली सरकार को भारी राजस्व देते हैं और नगर निगमों को सम्पति कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद जब दिल्ली सरकार को ठप्प पड़ गए उद्योगों के लिए राहत पैकेज लाना चाहिए था तब वह नया गैरकानूनी रखरखाव शुल्क लाद रही है।वहीं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि दशकों पुराने औद्योगिक क्षेत्रों पर आज रखरखाव शुल्क लगाने के पीछे केजरीवाल सरकार का कोई गुप्त एजेंडा लगता है, या तो सरकार उद्योग ठप करना चाहती है या राजनीतिक उगाही करना चाहती है।

सांसद प्रवेश ने कहा, शुल्क लगाने के पीछे केजरीवाल सरकार का कोई गुप्त एजेंडा

सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल सरकार जानती है कि रखरखाव शुल्क लगाने का प्रस्ताव न्यायालय में टिक नहीं सकता पर इसे लगाने के पीछे उसका कोई गुप्त एजेंडा है। या तो दिल्ली सरकार मंद व्यापार एवं लॉक डाउन का प्रभाव झेल रहे उद्योगपतियों को प्लाट बेचने को बाध्य करना चाहती है या फिर रखरखाव शुल्क नोटिसों का भय दिखा कर आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक चंदा उगाहना चाहती है।

बिजली उपभोक्ता किस्तों में जमा करा सकते हैं बकाया राशिः एनडीएमसी

नई दिल्ली (एसएनबी)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने इसी महीने यानी फरवरी में जारी बिजली के बिल के विविध/सीसीटीवी शुल्क के खाने में दर्ज शुल्क के भुगतान को किस्तों में देने की उपभोक्ताओं को फिहाल छूट दी है।

उपभोक्ता इस राशि का चार किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, पहली किस्त का भुगतान 28 फरवरी तक करना होगा। परिषद ने सफाई देते हुए कहा है कि बिल में दर्ज यह राशि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के 28 मार्च, 2018 के जारी टैरिफ के मुताबिक है। दरअसल एनडीएमसी ने उपभोक्ताओं को एक साथ पूरी राशि जमा कराने के लिए बिल भेजा है, लेकिन काउंसिल सदस्य गिरीष सचदेवा एवं कुलजीत चहल के दखल के बाद अधिकारियों ने इसे किस्तों में जमा कराने का निर्णय लिया है। जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल थोड़ा राहत मिली है। परिषद का कहना है कि इस राशि का सीसीटीवी शुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यह बकाया राशि एक अप्रैल, 2015 से एक अप्रैल, 2018 के जून, जुलाई, अगस्त 2020 तक की है। यह बकाया राशि 10 किलोवाट तक के व्यावसायिक कनेक्शनों पर है।